IJARSCT
International Journal of Advanced Research in Science, Communication and Technology
International Open-Access, Double-Blind, Peer-Reviewed, Refereed, Multidisciplinary Online Journal
ISSN: 2581-9429
Volume 6, Issue 11, June 2026
Impact Factor: 8.2

इक्कीसवीं सदी में भारत-चीन संबंधों का सामरिक एवं आर्थिक विश्लेषण

सुनील कुमार[1] and डॉ. रेखा रानी[2]
[1]शोधार्थी, राजनीति विज्ञान-विभाग
[2]प्रोफेसर, राजनीति विज्ञान-विभाग
सनराइज़ विश्वविद्यालय, अलवर, राजस्थान

सारांश

इक्कीसवीं सदी में भारत और चीन के संबंध एशिया ही नहीं बल्कि वैश्विक राजनीति एवं अर्थव्यवस्था के प्रमुख निर्धारकों में से एक बन गए हैं। दोनों देश विश्व की सबसे अधिक जनसंख्या वाले राष्ट्र होने के साथ-साथ तीव्र आर्थिक विकास, सैन्य आधुनिकीकरण तथा क्षेत्रीय एवं वैश्विक प्रभाव विस्तार की दिशा में अग्रसर हैं। एक ओर दोनों देशों के बीच व्यापार, निवेश, बहुपक्षीय सहयोग तथा जलवायु परिवर्तन जैसे विषयों पर सहयोग देखने को मिलता है, वहीं दूसरी ओर सीमा विवाद, हिंद-प्रशांत क्षेत्र में प्रतिस्पर्धा, समुद्री सुरक्षा, चीन-पाकिस्तान आर्थिक गलियारा, बेल्ट एंड रोड प्रारंभिक तथा वास्तविक नियंत्रण रेखा पर तनाव जैसे मुद्दों ने संबंधों को जटिल बनाया है। यह समीक्षा-पत्र इक्कीसवीं सदी में भारत-चीन संबंधों के रणनीतिक एवं आर्थिक आयामों का विश्लेषण करता है।

मुख्य संकेतक: सामरिक संबंध, आर्थिक सहयोग, सीमा विवाद, व्यापार, हिंद-प्रशांत, भू-राजनीति।

परिचय

भारत और चीन एशिया की दो प्राचीन सभ्यताएँ तथा वर्तमान समय की उभरती वैश्विक शक्तियाँ हैं। इक्कीसवीं सदी में दोनों देशों के बीच संबंधों ने अंतरराष्ट्रीय राजनीति एवं वैश्विक आर्थिक व्यवस्था को व्यापक रूप से प्रभावित किया है। दोनों देशों की संयुक्त जनसंख्या विश्व की लगभग एक-तिहाई जनसंख्या का प्रतिनिधित्व करती है तथा दोनों ही विश्व अर्थव्यवस्था के प्रमुख विकास इंजन माने जाते हैं। हालांकि, 1962 के

IJARSCT
International Journal of Advanced Research in Science, Communication and Technology
International Open-Access, Double-Blind, Peer-Reviewed, Refereed, Multidisciplinary Online Journal
ISSN: 2581-9429 Volume 6, Issue 11, June 2026 Impact Factor: 8.2

युद्ध के बाद से सीमा विवाद, सुरक्षा चिंताएँ तथा क्षेत्रीय प्रतिस्पर्धा दोनों देशों के संबंधों में निरंतर तनाव का कारण बनी हुई हैं।

दूसरी ओर, व्यापार, निवेश, ब्रिक्स, एससीओ तथा जी20 जैसे बहुपक्षीय मंचों पर दोनों देशों का सहयोग वैश्विक आर्थिक स्थिरता एवं विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। वर्तमान अध्ययन का उद्देश्य भारत-चीन संबंधों के रणनीतिक एवं आर्थिक आयामों की समीक्षा करना तथा उपलब्ध साहित्य के आधार पर इनके भविष्य की संभावनाओं का विश्लेषण करना है।

अध्ययन के उद्देश्य

1. इक्कीसवीं सदी में भारत-चीन संबंधों के विकास का विश्लेषण करना।
2. दोनों देशों के सामरिक संबंधों एवं सुरक्षा चुनौतियों का अध्ययन करना।
3. आर्थिक सहयोग एवं व्यापारिक संबंधों का मूल्यांकन करना।
4. सीमा विवाद एवं भू-राजनीतिक प्रतिस्पर्धा का विश्लेषण करना।
5. भविष्य की संभावनाओं एवं नीति सुझाव प्रस्तुत करना।

शोध पद्धति

यह अध्ययन द्वितीयक स्रोतों पर आधारित एक वर्णनात्मक एवं संख्यात्मक समीक्षा है। इसमें शोध पर्यावरण, पुस्तकालय, सरकारी विचार, नीति प्रकाशन तथा अंतरराष्ट्रीय संगठनों के प्रकाशनों का उपयोग किया गया है।

भारत-चीन संबंधों का ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य

स्वतंत्रता के पश्चात भारत और चीन ने पंचशील सिद्धांतों के आधार पर मैत्रीपूर्ण संबंध स्थापित करने का प्रयास किया। किन्तु 1962 के युद्ध ने दोनों देशों के संबंधों में गहरा अविश्वास उत्पन्न किया। 1988 में प्रधानमंत्री राजीव गांधी की चीन यात्रा के बाद संबंधों में सुधार प्रारंभ हुआ। इक्कीसवीं सदी में उच्च स्तरीय राजनीतिक संवाद, आर्थिक सहयोग तथा बहुपक्षीय मंचों पर सहभागिता बढ़ी, किंतु सीमा विवाद एवं सुरक्षा चिंताओं ने संबंधों को निरंतर प्रभावित किया।

IJARSCT
International Journal of Advanced Research in Science, Communication and Technology
International Open-Access, Double-Blind, Peer-Reviewed, Refereed, Multidisciplinary Online Journal
ISSN: 2581-9429 Volume 6, Issue 11, June 2026 Impact Factor: 8.2

सामरिक विश्लेषण

सीमा विवाद

भारत-चीन सीमा लगभग 3488 किमी लंबी मानी जाती है। लद्दाख, अक्साई चिन तथा अरुणाचल प्रदेश सीमा विवाद के प्रमुख क्षेत्र हैं। डोकलाम (2017) तथा गलवान घाटी (2020) की घटनाओं ने दोनों देशों के बीच विश्वास को गंभीर रूप से प्रभावित किया।

हिंद-प्रशांत रणनीति

भारत स्वतंत्र, मुक्त एवं समावेशी हिंद-प्रशांत क्षेत्र का समर्थन करता है, जबकि चीन अपनी समुद्री रणनीति एवं बेल्ट एंड रोड पहल के माध्यम से क्षेत्रीय प्रभाव बढ़ाने का प्रयास करता है। QUAD तथा चीन की समुद्री गतिविधियाँ इस प्रतिस्पर्धा को और अधिक स्पष्ट करती हैं।

सैन्य आधुनिकीकरण

भारत और चीन दोनों रक्षा बजट में निरंतर वृद्धि कर रहे हैं। चीन विश्व की दूसरी सबसे बड़ी सैन्य शक्ति के रूप में अपनी नौसेना, मिसाइल प्रणाली एवं साइबर क्षमताओं का विस्तार कर रहा है। भारत भी सीमा अवसंरचना, आधुनिक हथियारों तथा स्वदेशी रक्षा उत्पादन को मजबूत कर रहा है।

चीन-पाकिस्तान रणनीतिक सहयोग

चीन-पाकिस्तान आर्थिक गलियारा भारत की सामरिक चिंताओं का प्रमुख कारण है क्योंकि इसका एक भाग पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर से होकर गुजरता है। भारत इसे अपनी संप्रभुता के विरुद्ध मानता है।

आर्थिक विश्लेषण

इक्कीसवीं सदी में भारत और चीन के संबंधों का आर्थिक आयाम दोनों देशों के द्विपक्षीय संबंधों का सबसे महत्वपूर्ण और जटिल पक्ष बनकर उभरा है। एक ओर दोनों देश विश्व की सबसे तेज़ी से विकसित होने वाली अर्थव्यवस्थाओं में शामिल हैं तथा वैश्विक उत्पादन, व्यापार, निवेश और उपभोग के प्रमुख केंद्र बन चुके हैं, वहीं दूसरी ओर उनके आर्थिक संबंधों में सहयोग और प्रतिस्पर्धा का अद्वितीय मिश्रण दिखाई देता है। वर्ष 2000 के बाद भारत और चीन के बीच व्यापार में अभूतपूर्व वृद्धि हुई।

चीन भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक प्रतिष्ठान बना हुआ है, जबकि भारत चीन के लिए एक विशाल उपभोक्ता बाजार के रूप में विकसित हुआ। दोनों देशों की अर्थव्यवस्थाएँ वैश्विक आपूर्ति श्रृंखलाओं (ग्लोबल वैल्यू चेन) का महत्वपूर्ण हिस्सा बन चुकी हैं। चीन विश्व का प्रमुख विनिर्माण केंद्र (मैन्युफैक्चरिंग हब) है, जबकि भारत सेवा क्षेत्र, सूचना प्रौद्योगिकी, औषधि उद्योग तथा मानव संसाधन के क्षेत्र में अपनी विशिष्ट पहचान रखती है।

IJARSCT
International Journal of Advanced Research in Science, Communication and Technology
International Open-Access, Double-Blind, Peer-Reviewed, Refereed, Multidisciplinary Online Journal
ISSN: 2581-9429 Volume 6, Issue 11, June 2026 Impact Factor: 8.2

इस प्रकार दोनों देशों की आर्थिक संरचनाएं कई क्षेत्रों में एक-दूसरे की पूरक हैं, बावजूद उत्पादन क्षमता, औद्योगिक प्रतिस्पर्धा तथा व्यापारिक हितों के कारण कई क्षेत्रों में प्रतिस्पर्धा भी हैं। भारत-चीन व्यापार वर्ष 2000 में लगभग 3 अरब अमेरिकी डॉलर था, जो दो दशकों के भीतर बढ़कर 100 अरब अमेरिकी डॉलर से अधिक हो गया।

इस वृद्धि का प्रमुख कारण चीन से इलेक्ट्रॉनिक उपकरण, दूरसंचार उत्पाद, तांबे, विद्युत उपकरण, रसायन, औद्योगिक कच्चा माल तथा सौर ऊर्जा उपकरणों का आयात रहा। दूसरी ओर भारत से चीन को लौह अयस्क, पेट्रोकेमिकल उत्पाद, कपास, समुद्री उत्पाद तथा कुछ कृषि वस्तुओं का निर्यात किया जाता है। हालांकि व्यापार की मात्रा में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है, लेकिन भारत को लगातार बड़े व्यापार घाटे (व्यापार घाटा) का सामना करना पड़ा है। चीन से आयात की तुलना में भारत का निर्यात काफी कम है, जिसके कारण भारत का व्यापार घाटा निरंतर बढ़ता गया। यह व्यापार अनुवर्ती भारत की आर्थिक नीति निर्माताओं के लिए एक प्रमुख चिंता का विषय रहा है क्योंकि इससे विदेशी मुद्रा पर दबाव बढ़ता है तथा घरेलू उद्योगों पर प्रतिस्पर्धी प्रभाव पड़ता है।

विशेष रूप से इलेक्ट्रॉनिक्स, दूरसंचार उपकरण, सक्रिय औषधीय संघटक (API), सौर पैनल, ऑटोमोबाइल कलपुर्जे तथा तांबे के क्षेत्र में भारत की चीन पर निर्भरता अत्यधिक रही है। COVID-19 महामारी तथा वर्ष 2020 में गलवान घाटी संघर्ष के बाद भारत ने इस निर्भरता को कम करने के लिए 'आत्मनिर्भर भारत अभियान', 'मेक इन इंडिया' तथा उत्पादन आधारित प्रोत्साहन (PLI) जैसी योजनाओं को गति प्रदान की।

इन नीतियों का उद्देश्य घरेलू विनिर्माण क्षमता को बढ़ाना, आयात प्रतिस्थापन को प्रोत्साहित करना तथा वैश्विक आपूर्ति श्रृंखलाओं में भारत की भागीदारी को मजबूत करना था। चीन की बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव (BRI) और भारत की प्रतिबद्धताएं भी दोनों देशों के आर्थिक संबंधों को प्रभावित करती हैं। भारत ने BRI का समर्थन नहीं किया क्योंकि चीन-पाकिस्तान आर्थिक गलियारा पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर से उठता है, जिसे भारत अपनी संप्रभुता का उल्लंघन मानता है।

इसके विपरीत भारत ने अंतरराष्ट्रीय उत्तर-दक्षिण परिवहन गलियारा, चाबहार बंदरगाह परियोजना तथा इंडो-पैसिफिक आर्थिक सहयोग जैसे वैकल्पिक संपर्क नेटवर्क विकसित करने पर बल दिया। इस प्रकार आर्थिक अवसंरचना विकास भी दोनों देशों की रणनीतिक प्रतिस्पर्धा का महत्वपूर्ण माध्यम बन गया है। प्रत्यक्ष विदेशी निवेश के क्षेत्र में भी चीन ने भारत के प्रदूषण, मोबाइल फोन निर्माण, ई-कॉमर्स तथा डिजिटल भुगतान क्षेत्र में

IJARSCT
International Journal of Advanced Research in Science, Communication and Technology
International Open-Access, Double-Blind, Peer-Reviewed, Refereed, Multidisciplinary Online Journal
ISSN: 2581-9429 Volume 6, Issue 11, June 2026 Impact Factor: 8.2

उल्लेखनीय निवेश किया। कई प्रमुख भारतीय तकनीकी कंपनियों में चीनी फर्मों की महत्वपूर्ण गतिविधियां रही।

बहरहाल वर्ष 2020 के बाद भारत सरकार ने पड़ोसी देशों से आने वाले निवेश पर अतिरिक्त सरकारी प्रयासों को अनिवार्य बनाया तथा अनेक चीनी मोबाइल एप्लिकेशन पर राष्ट्रीय सुरक्षा के आधार पर प्रतिबंध लगाए। इससे दोनों देशों के निवेश संबंधों में नई चुनौतियाँ उत्पन्न हुईं। डिजिटल अर्थव्यवस्था और प्रौद्योगिकी प्रतिस्पर्धा इक्कीसवीं सदी में भारत-चीन आर्थिक संबंधों का एक नया आयाम बनकर सामने आया है।

5G तकनीक, कृत्रिम बुद्धिमत्ता, साइबर सुरक्षा, सेमीकंडक्टर्स, क्लाउड कंप्यूटिंग तथा डिजिटल अवसंरचना के क्षेत्रों में दोनों देश वैश्विक नेतृत्व प्राप्त करने का प्रयास कर रहे हैं। भारत ने डिजिटल सार्वजनिक अवसंरचना, यूनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेस, आधार तथा डिजिटल इंडिया कार्यक्रम के माध्यम से अपनी विशिष्ट पहचान स्थापित की है, जबकि चीन ने डिजिटल पेमेंट, ई-कॉमर्स, कृत्रिम बुद्धिमत्ता तथा स्मार्ट विनिर्माण के क्षेत्र में उल्लेखनीय प्रगति की है। वैश्विक आपूर्ति श्रृंखला पुनर्गठन की प्रक्रिया ने भारत के लिए नए अवसर उत्पन्न किए हैं। COVID-19 महामारी के बाद अनेक बहुराष्ट्रीय कंपनियों ने 'चीन प्लस वन' रणनीति अपनाई, जिसके तहत उत्पादन इकाइयों का आंशिक स्थानांतरण भारत, वियतनाम तथा अन्य एशियाई देशों की ओर किया गया। भारत ने इस अवसर का लाभ उठाने के लिए विनिर्माण क्षेत्र में सुधार, लॉजिस्टिक्स अवसंरचना, श्रम सुधार तथा विदेशी निवेश को आकर्षित करने हेतु कई नीतिगत परिवर्तन किए।

ऊर्जा, जलवायु परिवर्तन तथा हरित प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में भी दोनों देशों के आर्थिक हित महत्वपूर्ण हैं। चीन सौर ऊर्जा संयंत्र, बैटरी तथा इलेक्ट्रिक मोटर्स के उत्पादन में वैश्विक अग्रणी है, जबकि भारत नैनो ऊर्जा क्षमता के विस्तार तथा हरित ऊर्जा परिवर्तन पर विशेष बल दे रहा है। इस क्षेत्र में सहयोग की पर्याप्त संभावनाएं हैं, यद्यपि तकनीकी प्रतिस्पर्धा भी लगातार बढ़ रही है। बहुपक्षीय आर्थिक ढांचे में भारत और चीन की साझेदारी उनकी आर्थिक संबंधों का एक सकारात्मक पक्ष प्रस्तुत करती है। दोनों देश ब्रिक्स, शंघाई सहयोग संगठन (एससीओ), एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक (एआईआईबी), न्यू डेवलपमेंट बैंक (एनडीबी) तथा जी-20 जैसे मंचों पर वैश्विक आर्थिक शासन, विकास वित्त, जलवायु वित्त तथा विकासशील देशों के हितों की रक्षा के लिए सहयोग करते हैं।

इसके माध्यम से दोनों देशों ने पश्चिम-प्रधान आर्थिक व्यवस्था में सुधार तथा बहुध्रुवीय आर्थिक संरचना के निर्माण का समर्थन किया है। इसके बावजूद आर्थिक प्रतिस्पर्धा अनेक क्षेत्रों में स्पष्ट दिखाई देती है। वैश्विक निर्यात बाजार, विदेशी निवेश आकर्षित करने, तकनीकी नवाचार, विनिर्माण क्षमता तथा रणनीतिक खनिजों

IJARSCT
International Journal of Advanced Research in Science, Communication and Technology
International Open-Access, Double-Blind, Peer-Reviewed, Refereed, Multidisciplinary Online Journal
ISSN: 2581-9429 Volume 6, Issue 11, June 2026 Impact Factor: 8.2

की आपूर्ति के क्षेत्रों में दोनों देश एक-दूसरे के प्रमुख प्रतिस्पर्धी हैं। भारत अपनी जनसांख्यिकीय क्षमता, सेवा क्षेत्र, डिजिटल अर्थव्यवस्था तथा लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था के आधार पर निवेश आकर्षित करने का प्रयास कर रहा है, जबकि चीन अपनी उन्नत विनिर्माण क्षमता, विशाल अवसंरचना तथा निर्यात-उन्मुख औद्योगिक नीति के माध्यम से अपनी वैश्विक आर्थिक स्थिति को बनाए रखना चाहता है।

समग्र रूप से देखा जाए तो इक्कीसवीं सदी में भारत-चीन आर्थिक संबंध गहन परस्पर निर्भरता, तीव्र प्रतिस्पर्धा तथा सीमित सहयोग के त्रिकोण पर आधारित हैं। आर्थिक सहयोग दोनों देशों के विकास, क्षेत्रीय स्थिरता तथा वैश्विक आर्थिक वृद्धि के लिए आवश्यक है, किंतु व्यापार असंतुलन, निवेश संबंधी सुरक्षा चिंताएँ, तकनीकी प्रतिस्पर्धा तथा भू-राजनीतिक तनाव इन संबंधों को जटिल बनाते हैं। भविष्य में भारत के लिए आवश्यक होगा कि वह घरेलू विनिर्माण को सुदृढ़ करे, निर्यात विविधीकरण को बढ़ावा दे, तकनीकी आत्मनिर्भरता विकसित करे तथा बहुपक्षीय आर्थिक सहयोग के माध्यम से चीन के साथ संतुलित एवं व्यावहारिक आर्थिक संबंध बनाए रखे। इसी प्रकार चीन के लिए भी पारदर्शी व्यापार व्यवस्था, बाजार तक समान पहुँच तथा विश्वास-आधारित आर्थिक सहयोग को बढ़ावा देना दीर्घकालिक स्थिरता और एशियाई आर्थिक समृद्धि के लिए आवश्यक होगा।

द्विपक्षीय व्यापार

इक्कीसवीं सदी में भारत-चीन व्यापार में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है। चीन भारत का प्रमुख व्यापारिक साझेदार बन चुका है। भारत चीन से मुख्यतः इलेक्ट्रॉनिक्स, मशीनरी, रसायन एवं औद्योगिक उपकरण आयात करता है जबकि लौह अयस्क, पेट्रोकेमिकल उत्पाद तथा कृषि आधारित उत्पाद निर्यात करता है।

व्यापार असंतुलन

भारत लंबे समय से चीन के साथ बड़े व्यापार घाटे का सामना कर रहा है। इसका प्रमुख कारण चीन से उच्च मूल्य के विनिर्मित उत्पादों का आयात तथा भारत के सीमित निर्यात हैं।

निवेश एवं प्रौद्योगिकी

चीनी निवेश ने भारत के स्टार्टअप, मोबाइल निर्माण तथा डिजिटल क्षेत्र में महत्वपूर्ण योगदान दिया। किंतु 2020 के बाद राष्ट्रीय सुरक्षा कारणों से भारत ने प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (FDI) एवं चीनी मोबाइल एप्लिकेशन पर कई प्रतिबंध लगाए।

IJARSCT
International Journal of Advanced Research in Science, Communication and Technology
International Open-Access, Double-Blind, Peer-Reviewed, Refereed, Multidisciplinary Online Journal
ISSN: 2581-9429 Volume 6, Issue 11, June 2026 Impact Factor: 8.2

वैश्विक आपूर्ति श्रृंखला

कोविड-19 महामारी के बाद भारत ने "आत्मनिर्भर भारत", "मेक इन इंडिया" तथा उत्पादन आधारित प्रोत्साहन (PLI) योजनाओं के माध्यम से चीन पर निर्भरता कम करने का प्रयास किया।

बहुपक्षीय सहयोग

भारत और चीन ब्रिक्स, शंघाई सहयोग संगठन (SCO), G20 तथा एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक (AIIB) जैसे मंचों पर सहयोग करते हैं। जलवायु परिवर्तन, वैश्विक व्यापार सुधार तथा विकासशील देशों के हितों की रक्षा जैसे विषयों पर दोनों देशों की समान रुचि देखने को मिलती है।

प्रमुख चुनौतियाँ

1. सीमा विवाद एवं वास्तविक नियंत्रण रेखा पर तनाव।
2. व्यापार असंतुलन।
3. हिंद-प्रशांत क्षेत्र में रणनीतिक प्रतिस्पर्धा।
4. CPEC एवं BRI से संबंधित विवाद।
5. साइबर सुरक्षा एवं तकनीकी प्रतिस्पर्धा।
6. क्षेत्रीय प्रभाव विस्तार की प्रतिस्पर्धा।

भविष्य की संभावनाएँ

यदि दोनों देश सीमा विवादों का शांतिपूर्ण समाधान, व्यापार संतुलन, विश्वास निर्माण उपाय तथा नियमित कूटनीतिक संवाद को प्राथमिकता दें तो एशिया में स्थिरता एवं आर्थिक विकास को नई दिशा मिल सकती है। वैश्विक चुनौतियों जैसे जलवायु परिवर्तन, ऊर्जा सुरक्षा तथा आतंकवाद के विरुद्ध सहयोग दोनों देशों के दीर्घकालिक हित में होगा।

निष्कर्ष

इक्कीसवीं सदी में भारत-चीन संबंध सहयोग एवं प्रतिस्पर्धा के जटिल संतुलन का उदाहरण प्रस्तुत करते हैं। आर्थिक क्षेत्र में दोनों देशों की परस्पर निर्भरता निरंतर बढ़ी है, जबकि सामरिक क्षेत्र में सीमा विवाद, हिंद-प्रशांत प्रतिस्पर्धा तथा सुरक्षा चिंताओं ने संबंधों को चुनौतीपूर्ण बनाया है। भविष्य में संबंधों की स्थिरता इस बात पर निर्भर करेगी कि दोनों देश कूटनीतिक संवाद, विश्वास निर्माण तथा आर्थिक संतुलन के माध्यम से विवादों का समाधान किस प्रकार करते हैं। भारत को आर्थिक आत्मनिर्भरता, रक्षा आधुनिकीकरण तथा

IJARSCT
International Journal of Advanced Research in Science, Communication and Technology
International Open-Access, Double-Blind, Peer-Reviewed, Refereed, Multidisciplinary Online Journal
ISSN: 2581-9429
Volume 6, Issue 11, June 2026
Impact Factor: 8.2

बहुपक्षीय कूटनीति को सुदृढ़ करते हुए चीन के साथ संतुलित एवं व्यावहारिक संबंध विकसित करने की आवश्यकता है।

संदर्भ

1. बाजपेयी, के., हो, एस., और मिलर, एम. (2021). द रूटलेज हैंडबुक ऑफ़ चाइना-इंडिया रिलेशंस. रूटलेज.
2. गार्वर, जे. डब्ल्यू. (2016). चाइनाज क्वेस्ट: द हिस्ट्री ऑफ़ द फॉरेन रिलेशंस ऑफ़ द पीपल्स रिपब्लिक ऑफ़ चाइना. ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी प्रेस.
3. विदेश मंत्रालय. (2023). वार्षिक रिपोर्ट 2022-23. भारत सरकार.
4. पंत, एच. वी. (2022). इंडिया एंड चाइना: कॉम्पिटिशन एंड कोऑपरेशन इन द इंडो-पैसिफिक. रूटलेज.
5. स्कॉट, डी. (2019). इंडिया एंड द इंडो-पैसिफिक. रूटलेज.
6. स्मॉल, ए. (2015). द चाइना-पाकिस्तान एक्सिस. ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी प्रेस.
7. टेलिस, ए. जे. (2020). ट्रबल्स ऑन द हिमालयन बॉर्डर. कार्नेगी एंडोमेंट फॉर इंटरनेशनल पीस.
8. विश्व बैंक. (2023). वर्ल्ड डेवलपमेंट इंडिकेटर्स.
9. विश्व व्यापार संगठन. (2023). वर्ल्ड ट्रेड स्टैटिस्टिकल रिव्यू.
10. झांग, एल. (2021). इंडिया-चाइना इकोनॉमिक रिलेशंस इन द 21st सेंचुरी. जर्नल ऑफ़ कंटेम्पररी चाइना, 30(128), 231–247.